

# मुख्यमंत्री ने रिफाइनरी के पास पेट्रोजोन के भूमि आवंटन को स्वीकृति दी

## रीको को सोलर पार्क तथा चम्बल वृहद् पेयजल के लिये भी भूमि आवंटन को मंजूरी मिली

जयपुर, 13 जनवरी। मुख्यमंत्री भजलाल शर्मा ने राज्य में औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने, ऊर्जा और पेयजल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और युवाओं को रोजगार के अवसर में वृद्धि के उद्देश्य से महत्वपूर्ण निर्णय लिये हैं। शर्मा ने रीको को राजस्थान पेट्रोजोन और औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना के लिए, राजस्थान सोलर पार्क डवलपमेंट कंपनी लिमिटेड को सोलर प्रोजेक्ट की स्थापना के लिए तथा चंबल नदी आधारित वृहद् पेयजल योजना के लिए भूमि आवंटन की स्वीकृति प्रदान की है।

मुख्यमंत्री ने पचपदरा रिफाइनरी के पास राजस्थान पेट्रोजोन की स्थापना करने संबंधी बजट घोषणा

■ पेट्रोजोन के लिये पचपदरा के ग्राम सिन्धियों की ढाणी में 74 हेक्टेयर और ग्राम खेमाबाबा नगर में 102 हेक्टेयर भूमि आवंटन को स्वीकृति दी गई।

■ चम्बल-सवाई माधोपुर-करौली-नारौनी-गंगापुर सिटी की वृहद् पेयजल योजना के लिये वॉटर रिज़रवॉयर बनाने के लिये भंडारायल तहसील में 221 हेक्टेयर भूमि आवंटन की स्वीकृति दी गई।

को पूरा करते हुए, रीको को पचपदरा तहसील (बालोतरा) के ग्राम सिन्धियों की ढाणी में 74.50 हेक्टेयर भूमि और ग्राम खेमाबाबा नगर में 102 हेक्टेयर भूमि के आवंटन की स्वीकृति दी है। इससे रिफाइनरी के पास पेट्रोजोन की स्थापना का कार्य शीघ्र शुरू हो

सकेगा। शर्मा ने बजट घोषणा वर्ष 2024-25 के अन्तर्गत भीलवाड़ा जिले की जहाजपुर तहसील के ग्राम पीपलुन्द में नवीन औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना के लिए भी रीको को 31 हेक्टेयर भूमि आवंटित करने की स्वीकृति प्रदान की है। इसके साथ ही, उन्होंने 2000

मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट की स्थापना के लिए राजस्थान सोलर पार्क डवलपमेंट कंपनी लिमिटेड को जैसलमेर जिले की तहसील नाचाना के ग्राम बोडाना में 4 हजार हेक्टेयर राजकीय भूमि के आवंटन की स्वीकृति दी है।

एक अन्य प्रकरण में, बजट घोषणा वर्ष 2024-25 के अन्तर्गत चम्बल नदी आधारित वृहद् पेयजल परियोजना चम्बल-सवाईमाधोपुर-करौली-नादौती-गंगापुर सिटी की क्रियावित्ति के लिए वॉटर रिज़र्वेयर बनाने के लिए तहसील मधुदायल (करौली) के ग्राम पंचौली, दरगावा, फिरोजपुर और मारकाकुआ में 221 हेक्टेयर भूमि के आवंटन की स्वीकृति दी गई है।

## न स्वास्थ्य, न उम्र, ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

बना हुआ है। उस परिवार का उन पर भरोसा नहीं रहा है, क्योंकि वे ऐसे इकलौते नेता हैं, जिन्होंने सोनिया गांधी को आँखें दिखाई हैं तथा उस विश्वास को तोड़ा है, जो उस परिवार को उन पर था।

इसलिए, अगर गहलोलत ने दिल्ली के चुनावों को लेकर एक प्रैस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, तो सचिन पायलट से भी कहा गया है कि एक युवा नेता के रूप में, वे भी एक प्रैस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करें तथा यह घोषणा करें कि कांग्रेस दिल्ली के शिष्टित बेरोजगार युवाओं को एक वर्ष तक 85000 रूपए प्रतिमाह देगी।

गहलोलत इस समय मुश्किल में है क्योंकि उनका स्वास्थ्य, उनकी उम्र और गांधी परिवार से उनकी परेशानी- कोई भी चीज उनकी इस महत्वाकांक्षा का समर्थन नहीं कर रही कि वे पार्टी और राजनीति में प्रार्संगिक बने रहें।

## छात्र आंदोलन ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

का लाभ दे चुकी है, जबकि नरेश के अलावा शेष अन्य आरोपी अभी फरार चल रहे हैं। वहीं, साल 2004 में ही पुलिस ने विवि के बाहर रास्ता जाम करने के मामले में मामला दर्ज कर आरोपी नरेश मीणा की अनुपस्थिति में उसके खिलाफ आरोप पत्र पेश किया था। इस पर अदालत ने नरेश मीणा के गिरफ्तारी के स्थान पर वॉरंट जारी कर तलब किया था। पुलिस ने सोमवार को नरेश मीणा को जेल से प्रोडक्शन वॉरंट से लाकर अदालत में पेश किया था, जहां अदालत ने उसे 24 जनवरी तक जेल भेज दिया।

## सिंगापुर के...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आयेगा। उनका 16 जनवरी को राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में औपचारिक स्वागत किया जाएगा।

अपनी यात्रा के दौरान, शनमुगलम, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के साथ चर्चा करेंगे, जो उनके सम्मान में एक भोज का आयोजन भी करेंगी। वे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। इसके अलावा वे विदेश मंत्री एस. जयशंकर और कई अन्य भारतीय गणमान्य लोगों से भेंट करेंगी। वे 17-18 जनवरी को ओडिशा का भी दौरा करेंगी। यह राजकीय यात्रा भारत और सिंगापुर के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 60वीं वर्षगांठ के समारोहों की शुरुआत को भी चिह्नित करेगी।

ओडिशा के भुवनेश्वर में राष्ट्रपति शर्मन ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी से मुलाकात करेंगी।

# ‘सीएजी रिपोर्ट पेश करने में बरती जा रही ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

जिस तरह टालमटोल कर रही है उससे उसकी वास्तविकता को लेकर शक होता है आपको सीएजी रिपोर्टों को तुरंत विधानसभा अध्यक्ष को प्रेषित करना चाहिये था ताकि उस पर सदन में बहस करायी जा सके।

अदालत इस मामले की अगली सुनवाई 16 जनवरी को करेगी। दिल्ली सरकार की ओर से कहा गया कि यह याचिका राजनीति से प्रेरित है।

अदालत ने कहा कि इन रिपोर्टों को उपराज्यपाल को भेजने और फिर उन्हें विधानसभा अध्यक्ष को प्रेषित करने की तिथियाँ और उनमें लगने वाले समय को देखा जाये तो उससे सारी चीजें स्पष्ट लगती हैं।

अदालत ने कहा, देखिये आपने कुछ समय तक किस तरह टाल-मटोल की यह दुर्भाग्यपूर्ण है। अदालत ने टिप्पणी की कि यह टाल-मटोल सीएजी की रिपोर्टों के लिए बहस करने से

## हर मोर्चे पर असफल...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सरकार ने सीमा पर बड़ी संख्या में सैनिक तैनात कर दिये हैं, इसके साथ ही गोला-बारूद का बड़ा जखीरा वहाँ पहुँचा दिया गया है। कुछ नौसैनिक बल भी अतिरिक्त रूप से सक्रिय हो गये हैं तथा उन्होंने बंगाल की खाड़ी से भारतीय मछुआरे पकड़े हैं।

सही बात तो यह है कि बाँलादेश के सीमा सुरक्षा बलों तथा सेनाओं द्वारा भारतीय सेना पर सीधी लड़ाई के लिये दबाव बनाने में कोई संदेह नहीं रहा है। यह पूरी तरह सम्भव है कि बाँलादेश की अन्तरिम सरकार पर कम से कम कुछ क्षेत्रों में कुछ परिणाम प्रदर्शित करने का भारी दबाव है तथा इसलिए वह सरकार अपनी जनता को अपनी सैन्य दक्षता दर्शा रही है। कुछ छुट्टुपुट तथा आकस्मिक घटनाएँ घटित होने की कुछ संभावना हर समय है तथा ऐसी घटनाओं से अनावश्यक टकराव तथा दुश्मनी की स्थिति पैदा हो सकती है।

बाँलादेश में इस उग्र माहौल को शांत करने के प्रयास के अन्तर्गत, भारतीय डिप्टी हाईकमिश्नर ने मौजूदा तंत्र पर

बातचीत के लिये मंच उपलब्ध कराने पर बल दिया है।

बाँलादेश, भारत पर यह दबाव बनाने की कोशिश भी कर रहा है कि वह उनकी फरार नेता, शेख हसीना को बाँलादेश के सुपुर्द करे। बाँलादेशी अधिकारी शेख हसीना को वापस करने की मांग पहले ही कर चुके हैं। अब वे भारत में शेख हसीना की गिरफ्तारी के लिये 'रेड कॉर्नर' नोटिस जारी कराने के लिये इन्टरपोल भी जा रहे हैं।

हालाँकि, इन्टरपोल समझौते पर भारत के हस्ताक्षर हैं, फिर भी प्रत्येक भागीदार देश सभी 'रेड कॉर्नर' आवेदनों को अपने देश के कानून के आधार पर परखता है तथा किसी देश के लिये यह जरूरी नहीं है कि वह उस व्यक्ति को सौंप दे, जिसने उसके क्षेत्राधिकार में शरण ली है। यह असंभावनी है कि इन परिस्थितियों में, भारत शेख हसीना को बाँलादेशी अधिकारियों को सौंप देगा। इससे आगामी उस अवधि के दौरान दोनों देशों के रिस्ते खराब भी हो सकते हैं, जब तक वहाँ वर्तमान अन्तरिम सरकार का शासन है।

## हाईकोर्ट ने गंगापुर ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

रामकेश मीणा की ओर से दायर जनहित याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिनांक

सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता सारांश सेनी ने अदालत को बताया कि गंगापुर सिटी को जिले का दर्जा निर्धारित मापदंड के तहत दिया गया था। प्रदेश में सरकार बदलने के बाद जिलों को लेकर राजनीति शुरू हुई और अब राजनीतिक द्वेषता के चलते ही कुछ जिलों का दर्जा समाप्त कर दिया गया है। गंगापुर सिटी से जिला का दर्जा समाप्त करने के पीछे भी सरकार की राजनीतिक द्वेषता है। याचिका में कहा गया कि सरकार ने करीब डेढ़ साल पहले गंगापुर सिटी को जिला बनाया था और उसके बाद यहाँ कई प्रशासनिक नियुक्तियाँ हो चुकी हैं। यहाँ विभाग भी बतौर जिला स्तर पर काम कर रहे हैं। कमेटी ने लोगों से आपत्तियाँ मांगने के बाद इसे जिला घोषित किया था। ऐसे में अब महज राजनीतिक द्वेषता के चलते इसे जिला निरस्त करना गलत है।

# ‘ग्राँस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन इस वर्ष 6.4 प्रतिशत घटेगा’

-डॉ. सतीश मिश्रा-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 13 जनवरी। कांग्रेस ने आज केन्द्र सरकार से कहा कि भारतीय गरीब लोगों के लिए आमदनी का सहारा, मनरेगा की अधिक मजदूरी तथा बड़ा हुआ न्यूनतम समर्थन मूल्य- आज की बड़ी आवश्यकता हैं। पार्टी ने मांग की कि आगामी केन्द्रीय बजट में "हास्यास्पद रूप से जटिल" जी.एस.टी. व्यवस्था को सरल बनाया जाये तथा मध्यम वर्ग को इनकम टैक्स में राहत दी जाये।

कांग्रेस ने एक बयान में कहा कि वर्तमान राजस्व के लिये जी.डी.पी. ग्रोथ के अनुमानों में गिरावट को रोकने के लिए क्रांतिकारी कदम उठाने की जरूरत है, ताकि ग्रोथ में हो रही कमी तथा देश में निवेश में कमी होने की स्थिति खत्म हो सके।

ए.आई.सी.सी. महासचिव तथा मीडिया-प्रभारी जयराम रमेश ने कहा कि ऐसी स्थिति से केन्द्रीय बजट की बड़ी निराशाजनक पृष्ठभूमि बनती है। रमेश ने एक बयान में कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 में जी.डी.पी. ग्रोथ के लिये केन्द्र सरकार द्वारा जारी अग्रिम अनुमान में केवल 6.4 प्रतिशत ग्रोथ रहने का अनुमान है।

उन्होंने कहा, "यह चार साल की सबसे कम ग्रोथ है तथा वित्त वर्ष 2024 (2023-24) की 8.2 प्रतिशत ग्रोथ की तुलना में जबर्दस्त कमी दर्शाती है। यह हाल ही के आर.बी.आई. के अनुमान, 6.6 प्रतिशत ग्रोथ से भी कम है, जो पहले ही 7.2 प्रतिशत के पूर्व के अनुमान में कमी दर्शाने वाली थी। पिछले चन्द सप्ताहों में, भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति बिगड़ी तथा सबसे महत्वपूर्ण मैन्यूफैक्चरिंग क्षेत्र का विस्तार बंद हो गया है।

कांग्रेस नेता ने कहा कि सरकार ग्रोथ में स्लोडाउन और उसके विभिन्न आयामों से इन्कार करने की स्थिति में नहीं है।

रमेश ने मोदी सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि गत दस सालों में भारत की उपभोग की कहानी उलट आई है और अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन कर उभरी है। उन्होंने कहा, इस वर्ष की दूसरी तिमाही के आँकड़ों के अनुसार, प्राइवेट फाइनेल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर

## कांग्रेस का आरोप है कि ग्रोथ में भारी गिरावट आई है और सरकार इससे इन्कार नहीं कर सकती है

■ कांग्रेस ने यह भी कहा कि मनरेगा की दिहाड़ी में वृद्धि और कृषि उपज की एमएसपी बढ़ाना जरूरी है ताकि गरीबों की आय में वृद्धि हो सके।

■ कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने प्राइवेट फाइनेल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में गिरावट का उल्लेख करते हुए कहा है, इस बार कारों की बिक्री चार साल के न्यूनतम स्तर पर रही।

■ कांग्रेस ने मिडिल क्लास की घरेलू बचत कम होने पर भी चिंता जताई और कहा कि सरकारी आंकड़े ही कह रहे हैं कि 2020-21 और 2022-23 के बीच घरेलू बचत 9 लाख करोड़ रूपए घटी है।

(पी.एफ.सी.ई.) पूर्व तिमाही के 7.4 प्रतिशत से घट कर 6 प्रतिशत रह गया है। कारों की बिक्री चार साल में सबसे निचले स्तर पर रही। भारत के कई प्रमुख उद्योगपतियों ने संकुचित होते मध्यम वर्ग पर चिंता जताई। उपभोग में स्थिरता से जी.डी.पी. ग्रोथ रेट्स घिसट रही हैं, यही वजह है कि प्राइवेट सेक्टर नई उत्पादन क्षमता में निवेश करने को इच्छुक नहीं है।

कांग्रेस महासचिव ने निजी निवेश में सुस्ती की ओर भी इशारा किया व कहा कि "सरकार का अनुमान था कि सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में समग्र ग्रोथ के बारे में अनुमान था कि यह गत वर्ष के 9 प्रतिशत से घट कर 6.4 प्रतिशत हो जाएगी।"

उन्होंने कहा, यह आँकड़ा भी भारत में निवेश करने की निजी क्षेत्र की अनिच्छा को ढकने का इशारा करता है। उन्होंने कहा, सरकार का अपना इकोनॉमिक सर्वे मानता है कि मशीनरी और उपकरण तथा बौद्धिक संपदा से प्राइवेट सैक्टर के ग्राँस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन (जी.एफ.सी.एफ.) से वित्त वर्ष 2022-23 तक मात्र 35 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है, जो अच्छा नहीं कहा सकता। स्थिति और बिगड़ी है और निजी क्षेत्र द्वारा वित्त वर्ष 2023 और वित्त वर्ष 2024 में नई योजनाओं की घोषणा के 21 प्रतिशत की कमी हुई है। निजी क्षेत्र की नई उत्पादन क्षमता में

निवेश की अनिच्छा दर्शाती है कि हमारी मध्यकालिक ग्रोथ और ज्यादा प्रभावित होगी।

रमेश ने कहा, 2024-25 के केन्द्रीय बजट में 11.11 लाख करोड़ रूपए के आवंटन के साथ पूँजी निवेश में बढ़ोतरी के बड़े-बड़े वादे किए गए थे। तथापि, नवम्बर तक, केवल 5.13 लाख करोड़ रूपए ही खर्च किए गए। रमेश ने यह भी दावा किया कि यह पिछले वर्ष की तुलना में 12 प्रतिशत कम था।

उन्होंने दावा किया, "अधिकतर आकलन संकेत देते हैं कि वित्तीय वर्ष के अंत तक सरकार लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाएगी। अपने फंड खर्च करने में सरकार की अक्षमता कुछ हद तक व्यापक आर्थिक निराशा के लिए जिम्मेवार है।"

"परिवार की सिकुड़ती बचत" की बात करते हुए, उन्होंने कहा कि सरकार का स्वयं का डेटा दिखाता है कि 2020-21 और 2022-2023 के बीच परिवारों की नेट वित्तीय बचत में 9 लाख करोड़ की कमी आई।

उन्होंने कहा, परिवार के वित्तीय उत्तरदायित्व जी.डी.पी. का 6.4 प्रतिशत थे, जो कि कई दशकों में सर्वाधिक हैं। रमेश ने कहा, "कोविड-19 पैन्डेमिक के समय की नीतियों की असफलता अभी भी भारत के परिवारों को परेशान कर रही है। यह पृष्ठभूमि है, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आगामी बजट की। जैसा कि नेशनल

कांग्रेस ने निरंतर कहा है, ग्रोथ स्लोडाउन और निवेश निरुत्साह के बादलों को हटाने के लिए क्रांतिकारी कदम उठाने की आवश्यकता है।" उन्होंने कहा, भारत के गरीबों के लिए आय में सहायता, मनरेगा में दिहाड़ी बढ़ाने और कृषि उपज की एम.एस.पी. बढ़ाना समय की जरूरत है, हास्यास्पद रूप से जटिल जी.एस.टी. प्रणाली का सरलीकरण और मध्यम वर्ग के लिए इनकम टैक्स में राहत भी जरूरी है।

## लम्बे रोड शो के कारण आतिशी नामांकन नहीं भर सकीं

नयी दिल्ली, 13 जनवरी। आम

आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता एवं दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने सोमवार को नामांकन से पहले लंबा रोड शो, किया लेकिन नामांकन नहीं दाखिल कर सकीं। आतिशी ने नामांकन से पहले लंबा रोड शो किया लेकिन मध्यम वर्ग के लिए आयोग पहुंचना था, इसलिए नामांकन नहीं कर सकीं। इससे पहले, उन्होंने आप नेता मनीष सिंसोदिया के साथ गिरि नगर स्थित गुरुद्वारा गुरु गोविंद साहिब में मत्था टेका और कालकाजी मंदिर में पूजा-अर्चना की और अपने अभियान के लिए आशीर्वाद मांगा।

## महाकुंभ ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

जुड़े हुए हैं, और यहां आना उनके लिए सौभाग्य की बात है। भारतीय संस्कृति, अध्यात्म और आस्था का प्रतीक यह मेला हर 12 वर्ष पर आयोजित होता है। महाकुम्भ भारत की पौराणिक परम्पराओं और आध्यात्मिक विरासत का उत्सव है। आज प्रथम स्नान को लेकर भी लोगों में जोश और उत्साह देखा जा रहा है। यहां आये श्रद्धालु चाहे, वे जिस भी किसी आयु वर्ग के हों, उनके अंदर पावन महाकुम्भ में स्नान करके पुण्य-लाभ के भागी बनने की इच्छा स्पष्ट नजर आ रही है।



राजस्थान सरकार



एक वर्ष परियाम उत्कर्ष

# पटेल नगर

## आवासीय योजना

(खोरी-रोपाड़ा) जोन-10

(रेरा रजिस्ट्रेशन नं. RAJ/P/2023/2588)

# 270 भूखण्डों

के लॉटरी से आवंटन हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रारम्भ

आवेदन की प्रारम्भ तिथि	: 14.01.2025
आवेदन की अन्तिम तिथि	: 13.02.2025
लॉटरी की तिथि	: 24.02.2025

आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु जविप्रा की वेबसाइट [www.jda.rajasthan.gov.in](http://www.jda.rajasthan.gov.in) अथवा ई-मित्र कियोस्क केन्द्रों पर उपलब्ध हैं।

RERA Website : <http://rera.rajasthan.gov.in>






## जयपुर विकास प्राधिकरण

इन्दिया सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004